दिल्ली, नोएडा, साहिबाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर, लोनी, मेरठ, हापुड़ से एक साथ प्रसारित

विशेष खबर

हर खबर की रखे खबर

विशेष खबर visheshkhabar

• वर्ष: • 2 अंक: 16

पृष्ठ : 8

गाजियाबाद

16 से 31 दिसंबर-2019

मूल्य: 10 रुपये

पाक्षिक समाचार पत्र

visheshkhabarvk@gmail.com RNI: UPHIN/2017/74151

अन्दर के पेजों पर

3 कूड़ा उठाकर राजस्व जुटाएगी ईस्ट एमसीडी

5 मोदी की रैली से दिल्ली बीजेपी को मिली संजीवनी

7 अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए तो मोदी सरकार सबसे लाजवाब

8 2020 में बदल जाएगी गाजियाबाद की तस्वीर

नागरिकता कानून और एनआरसी से क्यों डरे हैं मुस्लिम

बवाल क्यों ?

विशेष संवाददाता

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद मोदी सरकार को संसद में दूसरी बड़ी कामयाबी मिली जब उसने नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को दोनों सदनों से पारित करा लिया। लेकिन विपक्ष द्वारा फैलाए गए भ्रम के कारण इस कानून को समझे बिना एक खास समुदाय के लोग देश के कई हिस्सों में विरोध और प्रदर्शन पर उतारू हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक संसद से सड़क तक इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि नागरिकता कानून किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का प्रोपेगेंडा इतना व्यापक है कि विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध की शुरुआत हुई पूर्वोत्तर भारत से खास तौर से असम में इसे लेकर बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली की जेएनयू और जामिया यूनिवर्सिटी समेत देश के कई स्कूल कालेजों में विरोध प्रदर्शन हुए। कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए जिस कारण सुरक्षा एजेंसियों को कानून व्यावस्था बनाने के सख्ती करनी पड़ी। पुलिस की सख्ती की असल वजह ये भी रही कि धीरे-धीरे खुलासा हो रहा है कि इस हिंसक विरोध के पीछे कुछ असामाजिक शक्तियों का हाथ है। लेकिन जिस नागरिकता कानून को लेकर देश भर में विरोध हो रहे हैं, वो कानून क्या पहले ये समझना जरूरी है।

नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 में क्या है?

भारत के पूर्वोत्तर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध होता रहा है जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से गैर-मुसलमान अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नियमों में ढील देने का प्रावधान है। इस कानून में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख) से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है। अब तक किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, नए कानून में समयावधि 11 से घटाकर 6 साल कर दी गई है।

विपक्ष फैला रहा भ्रम

विपक्षी पार्टियों इस कानून के मुसलमानों के खिलाफ बताकर भ्रम फैला रही है और उन्हें बता रही है कि ये कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है। क्योंकि इसमें मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। बिल का विरोध यह कहकर किया जा रहा है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव कैसे कर सकता है? वास्तिवकता ये है कि लोग विरोध कर रहे है उन्हें मालूम नहीं कि इस कानून से उनका कितना नफा नुकसान है। वे सिर्फ विपक्षी नेताओं के बरगलाने पर सड़को पर उतर रहे हैं।

नागरिकता कानून के नाम पर एनआरसी का विरोध

भले ही लोग नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन असल में वह विरोध कर रहे हैं एनआरसी का। क्योंकि लोग मान रहे हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग कह रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून में मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया गया है? उनका आरोप है कि ये सरकार मुस्लिमों की नागरिकता छीनना चाहती है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार एनआरसी से बाहर हुए हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता दे देगी, जबकि उसमें शामिल मुस्लिमों को देश से बाहर निकाल देगी।

क्या है एनआरसी

एनआरसी यानी नेशनल सिटिजन रजिस्टर। इसे आसान भाषा में भारतीय नागरिकों की एक लिस्ट समझा जा सकता है। एनआरसी से पता चलता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं, उसे अवैध निवासी माना जाता है।

असम भारत का पहला राज्य है जहां वर्ष 1951 के बाद एनआरसी लिस्ट अपडेट की गई। असम में नेशनल सिटिजन रजिस्टर सबसे पहले 1951 में तैयार कराया गया था और ये वहां अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की कथित घुसपैठ की वजह से हुए जनांदोलनों का नतीजा था।

इस जन आंदोलन के बाद असम समझौते पर दस्तखत हुए थे और साल 1986 में सिटिजनशिप एक्ट में संशोधन कर उसमें असम के लिए विशेष प्रावधान बनया गया।

इसके बाद साल 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू के साथ-साथ केंद्र ने भी हिस्सा लिया था। इस बैठक में तय हुआ कि असम में एनआरसी को अपडेट किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट पहली बार इस प्रक्रिया में 2009 में शामिल हुआ और 2014 में असम सरकार को एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। इस तरह 2015 से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह पूरी प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हुई। 31 अगस्त 2019 को एनआरसी की आखिरी लिस्ट जारी की गई और 19,06,657 लोग इस लिस्ट से बाहर हो गए। हांलाकि मोदी सरकार चाहती है पूरे देश में एनआरसी लागू हो लेकिन साथ ही सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि अभी न तो इस पर कानून बना है न ही इसका खाका तैयार किया गया है। लेकिन इस प्रस्तावित कानून के लिए सरकार ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि इससे किसी भी धर्म के लोगों खासकर मुस्लिमों को डरने की जरूत नहीं है। क्योंकि इसका प्रारूप पूर्वोत्तर एनआरसी से अलग होगा। जिसमें कोई भी उपलब्ध दस्तावेज यहां तक की किसी की गवाही भी नागरिकता का आधार हो सकती है। जब तमाम शंकाओं पर सरकार लोगों को आश्वस्त कर रही है तो समझ नहीं आ रहा कि लोग विपक्ष के बहकावे में आकर हिसंक विरोध प्रर्दशन क्यों कर रहे हैं।

एनआरसी में धर्म विशेष के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। एनआरसी में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर कहा जाए कि और धर्म के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। सभी नागरिक भले ही उनका धर्म कुछ भी हो, एनआरसी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एनआरसी अलग प्रक्रिया है और नागरिकता संशोधन विधेयक अलग प्रक्रिया है। इसे एक साथ नहीं रखा जा सकता।

अमित शाह, केन्द्रीय गृहमंत्री

संपादकीय

झारखंड में कहां हो गई भाजपा से चूक

भाजपा के रणनीतिकार अब इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि भाजपा को पिछले एक साल से लगातार हार मिल रही है और उसके हाथ से राज्यों की सत्ता फिसल रही है। जबकि कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है। असल में भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि भाजपा कई राज्यों में सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने में विफल रही है और जिसके कारण वह सत्ता से बाहर हो रही है। कुछ ऐसा ही झारखंड में देखने को मिला है। जहां पर भाजपा सहयोगी दलों के साथ गठबंधन नहीं बना सकी और उसका वोट बैंक बिखर गया।

विनीतकांत पाराशर

झारखंड में बीजेपी की सफलता के अश्वमेघ का घोड़ा आकर यकायक क्यों ठिठक गया। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में बीजेपी को मिले जितने वोट को आधार बनाया जाय तो झारखंड में पार्टी को साठ से ज्यादा सीटें मिलती। उसी बीजेपी को आखिर हुआ क्या, कैसे एक जोरदार पार्टी मई की गगनभेदी जीत के बाद यहां पाताल में आ गिरी, आखिर कहां चूक हुई है, इस पर मंथन होना बेहद जरूरी है। क्योंकि सबसे ज्यादा सीट और सबसे ज्यादा वोट पाने वाली बीजेपी का सत्ता यूं गवां देना सबकों अचरज में डाल रहा है।

देश में इस वक्त एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी की आभा और कामकाज से देश ही नहीं पूरा वैश्विक समुदाय अभीभूत है। इसके बावजूद एक ही साल में पांच राज्यों से भगवा झंडा क्यों उतरा और झारखंड में विकास के बेहतरीन कार्यों के बावजूद बीजेपी की पराजय पर पार्टी थिंक टैंक सोचने पर मजबूर हो गए हैं।

झारखंड की जीत दरअसल इशारा करती है कि आदिवासी महत्वाकांक्षाओं को ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जेएमएम की जोरदार वापसी इसी ओर इशारा करती है। दरअसल, यहां बीजेपी ने गैरआदिवासी राजनीति को आधार बनाकर गैर आदिवासी रघुवार दास को राज्य की कमान सौंपी थी। जानकार मानते हैं कि आदिवासियों में रघुवर सरकार के आदिवासियों पर ध्यान न देने की शिकायत थी। साथ ही आदिवासी अपने बीच से ही कोई बड़ा नेता चाहते थे। जेएमएम की वापसी इसी बात का प्रमाण है।

आदिवासी बहुल झारखंड में बीजेपी ने एक गैर आदिवासी सीएम केंडिडेट क्यों बनाया? इसके पीछे बीजेपी की जो मास्ट्रर स्ट्रोक स्ट्रेटजी थी, लगता है वो यहां कामयाब नहीं हुई। जो फामूर्ला देकर बीजेपी ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र लगातार जीता था, अब वही स्ट्रेटजी नाकाम हो गई। असल में बीजेपी ने नए राज्यों में अपनी पकड़ बनाने के लिए नए राजनीतिक ध्रुव बनाने की कोशिश की थी, इसके लिए राज्य की राजनीति को प्रभावित करने वाले जातीय क्षत्रपों से इतर नए क्षत्रपों को सत्ता की कमान सौंपी गई, लेकिन झारखंड के परिणाम ने स्पष्ट कर दिया कि ये स्ट्रैटजी गलत रही।

अगर हम पीछे मुड़ कर देखें तो पता चलेगा कि बीजेपी ने अधिकतर राज्यों में अपना आधार वहां मौजूद प्रमुख और प्रभावी जातिगत या क्षेत्रीय समूहों के इतर बनाया है। उदाहरण के लिए लंबे वक्त तक पटेलों का गुजरात की राजनीति में प्रभुत्व रहा, लेकिन नई व्यवस्था में पटेल समुदाय का सीएम नहीं है। बीजेपी की इस नीति के चलते उन्हें लंबे समय बाद गुजरात में कांग्रेस से बड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। हार्दिक पटेल बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर उभरे। आखिर क्यों फेल हो रही डबल इंजन थ्योरी को जानना भी अहम है। यानि पीएम मोदी का जनता के से ये अपील करना कि केन्द्र के साथ राज्य में बीजेपी की सरकार हो तो विकास की गति बेहतर होगी। लेकिन हाल में सामने आए विधानसभा के नतीजों से ये लगने लगा कि जनता ने डबल इंजन फॉमूर्ले को तो अपनाया लेकिन ये भी साफ कर दिया कि डबल इंजन में एक फुंका हुआ इंजन नहीं चलेगा? झारखंड में हार के पीछे ये अहम फैक्टर माना जा रहा है। कहीं न कहीं जनता ने रघुबर दास की सरकार में हुए कामकाज पर भरोसा नहीं जताया। वहीं, झारखंड चुनाव में स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों को उठाए जाने का भी असर नतीजों में दिखा, क्योंकि प्रदेश में स्थानीय मुद्दे बेहद अहम रोल निभाते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से कहां पर गलती हुई है कि दो साल में झारखंड समेत सातवां राज्य उसके हाथ से निकल गया। महज दो माह के भीतर पहले महाराष्ट्र में सत्ता बेदखल होने के बाद बीजेपी अब झारखंड में भी सत्ता से बाहर हो गई है।

भाजपा के रणनीतिकार अब इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि भाजपा को पिछले एक साल से लगातार हार मिल रही है और उसके हाथ से राज्यों की सत्ता फिसल रही है। जबकि कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है। असल में भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि भाजपा कई राज्यों में सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने में विफल रही है और जिसके कारण वह सत्ता से बाहर हो रही है। कुछ ऐसा ही झारखंड में देखने को मिला है। जहां पर भाजपा सहयोगी दलों के साथ गठबंधन नहीं बना सकी और उसका वोट बैंक बिखर गया।

अगर भाजपा मिलकर चुनाव लड़ती तो आज स्थिति अलग होती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले साल तक अजेय माने जा रहे थे, लेकिन पिछले एक साल दौरान भाजपा के हाथ से पांचवा राज्य फिसल गया। जबकि इन राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई है। हालांकि दो राज्यों में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के पीछे है। लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद ये तीसरा राज्य है जहां कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो रही है। फिलहाल भाजपा अब दिल्ली और बिहार की तैयारी में जुट गई है।

हांलाकि एक सत्य ये भी भाजपा के रणनीतिकार स्वीकार कर रहे हैं कि सहयोगी दल पीएम मोदी की स्वीकार्यता मानकर अपनी जीत के पीछे उनका हाथ मानने के बावजूद भाजपा पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही झारखंड में भी हुआ। आजसू ने ज्यादा सीटें देने की जिद्द न की होती तो दोनों का गठबंधन कभी न टूटता। आजसू का बीजेपी से हटकर जो हश्र हुआ वो भी सबने देख लिया। लेकिन रणनीतिकार इसके बावजूद मान रहे है कि गठबंधन के साथियों की दबाव की राजनीति के बावजूद उन्हें साथ जोडकर रखने की प्राथमिकता पर काम किया जाएगा। बिहार में फिर ये दबाव देखने को मिल सकता है लेकिन बीजेपी को हर हाल में जूडीयू को साधना पडेगा।

कूड़ा उठाकर राजस्व जुटाएगी ईस्ट एमसीडी

योजना से शहर भी स्वच्छ होगा, रेवेन्यू भी मिलेगा

मेयर अंजु कमलकांत

संवाददाता

पूर्वी दिल्ली। ईस्ट एमसीडी ने अपनी माली हालत सुधारने के लिए लोगों से उनके घरों से निकलने वाले कूड़े के कलेक्शन की एवज में चार्ज वसूलने की योजना बनाई है। इस योजना को किसी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत ईस्ट दिल्ली की अलग अलग कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से कम से कम 50 रुपये और अधिक से अधिक 200 रुपये वसूलने की योजना है। अभी तक जो संस्थान अपना कूड़ा बाहर सड़क पर या किसी अन्य माध्यम से ढलाव वगैरह पर डालकर निश्चित हो जाते थे, अब उन्हें भी अपने कूड़े के ठिकाने लगाने की एवज में जेबें ढीली करनी होगी। इस योजना को लेकर एमसीडी अधिकारियों से लेकर नेता बहुत उत्साहित हैं।

आर्थिक तंगी से जूझ रही ईस्ट एमसीडी के पास रेवेन्यू जुटाने के जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, उनके मुकाबले खर्चा बहुत अधिक है। अक्सर देखा गया है कि ईस्ट एमसीडी के पास अपने कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं होता। फंड के लिए एमसीडी को दिल्ली सरकार का मुंह ताकना पड़ता है। फंड को लेकर लगातार एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं। इन सबके बावजूद ईस्ट एमसीडी अपनी माली हालत सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए आमदनी बढ़ाने के लिए एमसीडी लगातार कई योजनाएं भी लेकर आ रही हैं। डोर टु डोर कूड़ा कलेक्शन योजना भी इसी का हिस्सा है। ईस्ट एमसीडी के सीनियर अधिकारी ने बताया कि अभी तक एमसीडी सीधे रूप से लोगों से कूड़ा उठाने का कोई चार्ज नहीं वसूलती। वहीं हर रोज लोगों के घरों से निकलने वाले 2000 मीट्रिक टन कूड़े को घरों से लेकर ढलाव और वहां से लैंडफिल सहित अन्य साइटों तक पहुंचाने के लिए पूरा अमला लगाना पड़ता है, जिसमें सफाई कर्मचारियों से लेकर ऑटो टिप्पर, ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रक, लोडर, ई रिक्शा और साइकल रिक्शा वगैरह शामिल हैं। इन सब पर एमसीडी को सालाना 200 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस खर्च का भार कम करने के लिए एमसीडी ने कूड़ा कलेक्शन करने पर चार्ज लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए पूरी योजना पर तेजी से काम चल रहा है। अधिकारी ने बताया बहुत से ऐसे सरकारी और गैर सरकारी संस्थान थे, जिनसे कूड़े का कोई शुल्क नहीं वसूला जा रहा था। जबकि इनसे भारी मात्रा में कूड़ा निकलता है।

किससे कितना चार्ज वसूला जाएगा

यूनिट चार्ज	(रुपयों में)
50 वर्गमीटर का घर	50
50 वर्ग मीटर से 200 मीटर	100
200 वर्गमीटर से अधिक	200
ढाबे और हलवाई	500
गेस्ट हाउस और धर्मशाला	2000
हॉस्टल	2000
50 लोगों के सीटिंग वाले रेस्टोरेंट	2000
50 लोगों की सीटिंग से अधिक	3000
थ्री स्टार होटल और बगैर स्टार वाले	3000
थ्री स्टार से ऊपर वाले होटल	5000
सरकारी और प्राइवेट ऑफिस	2000
क्लीनिक और लैब वगैरह	2000
लघु और कुटीर उद्योग	3000
गोदाम और कोल्ड स्टोरेज	5000
विवाह पार्टी हॉल और लोन वगैरह	5000
क्लब सिनेमा हॉल पब्स वगैरह	4000

अनारकली वार्ड में निगम पार्षद ने लगवाया हाउस टैक्स कैंप

पूर्वी दिल्ली। अनारकली वार्ड 22ई के लोगों की सुविधा के लिए अनारकली वार्ड से निगम पार्षद रेखा दीक्षित ने अनारकली वार्ड की जगतपुरी टेडर्स एसोसिएशन के कार्यालय में संपत्ति कर आम माफी योजना 2019-20 के अंतर्गत हाउस टैक्स कैम्प का आयोजन किया। कैंप में भारी संख्या में क्षेत्र की जनता ने ब्याज व जुमार्ने पर 100% छूट का लाभ उठाते हुए संपत्ति कर जमा करवाया। निगम के अधिकारियों ने संपत्ति कर शिविर में आए लोगों के फॉर्म भरे व चैक प्राप्त किए। एकदिवसीय कैंप में सैकड़ों की संख्या में आए लोगों ने संपत्ति कर शिविर में छूट का लाभ उठाया। नगर निगम को 8 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई। क्षेत्रीय निगम पार्षद रेखा दीक्षित का कहना था कि जिन लोगों ने आज तक कभी भी किसी कारण वश टैक्स नही भरा था उन सभी ने कैम्प का भरपूर लाभ उठाया।

इस मौके पर जगत पुरी टेडर्स एसोसिएशन आरडब्लूए के प्रधान के.सी.गुप्ता, युतिन्द्र शर्मा, मोहित गुप्ता, मंजू गुप्ता, उमा खन्ना, मुस्कान अग्रवाल, राकेश दीक्षित, अनिल गोयल, प्रवीण गुप्ता, आदि गणमान्य व्यक्ति व निगम से हाउस टैक्स निरीक्षक अतुल शर्मा, सहायक पवन, विजेंद्र आदि अधिकारी मौजूद रहे।

लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विवादों से नहीं छूट रहा पीछा

फूड इंसपेक्टर विवाद के बाद अब नगरपालिका चेयरमैन से तनातनी से सुर्खियों में

संवाददाता

लोनी पालिका चेयरमैन रंजीता धामा और उनके पति मनोज धामा

लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर

गाजियाबाद। लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का विवादों से पीछा छूटने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले एक फूड इंस्पेक्टर से हुए विवाद में एफआईआर के बाद पार्टी और प्रदेश सरकार से उनकी तनातनी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब लोनी नगर पालिका चेयरमैन से विवाद के कारण वे फिर सुर्खियों में है।

पिछले डेढ महीने से विधायक नंदकिशोर गुर्जर लगातार सुर्खियों में हैं। बता दें कि लोनी में तैनात फूड इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह का एक वीडियो सामने आया था। जिसमें आरोप है कि विधायक नंद किशोर ने उन्हें अपने कार्यालय बुलाकर मीट के होटलों के लाइसेंस न बनाने का दबाव डाला। कानून के तहत काम करने की बात पर विधायक ने मारपीट की। फूड इंसपेक्टर की शिकायत के बाद एसपी ग्रामीण की जांच व संस्तुति पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर व उनके साथियों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 323, 504, 506 और 332 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामलें में विधायक प्रतिनिधि की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसके कुछ दिन बाद जमानत भी हो गई।

इस मामलें में जब यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर ने विधायक नंद किशोर जवाब तलब किया तो मामले ने सियासी रंग ले लिया। दरअसल विधायक पर यह कार्रवाई उनके खिलाफ मिल रही शिकायतों और मीडिया में आए उनके पार्टी व सरकार के खिलाफ उनके वक्तव्यों के आधार पर की गई है।

दरअसल, विधायक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख कर कहा कि उन पर ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे वे आजीवन जेल में रहें और उनका जीवन सुरक्षित रह सके, क्योंकि कुछ लोग उनकी हत्या कराना चाहते हैं। पत्र में उन्होंने जिलाध्यक्ष व पूर्व नगर पालिका चेयरमैन पर भी आरोप लगाए कि ये लोग अधिकरियों से सांठगांठ कर उनकी छवि को बदनाम करने का काम कर रहे हैं।

विधायक नंद किशोर गुर्जर उस वक्त और ज्यादा सुर्खियों में आ गया जब विधान सभा सत्र के दौरान वे कुछ विधायकों के साथ अपने प्रकरण को लेकर धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री से मिलकर खेद व्यक्त कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोनी विधायक की शिकायतों को सुनकर जल्द ही उनका निवारण करने का आश्वासन दिया था। लेकिन बावजूद इसके लोनी विधायक के पीछे लगे विवादों का अंत नहीं हुआ। इसी के बाद से लोनी नगर पालिका की चेयरमैन रंजीता धामा और नंदकिशोर गुर्जर के बीच हो रही बयानबाजी सुर्खियों में छायी हुई है। रंजीता धामा ने विधायक पर अपनी हत्या कराने की आशंका जताकर पुलिस से सुरक्षा की मांग कर डाली है।

दरअसल विवाद के पीछे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पूर्व नगरपालिका चेयरमैन मनोज धामा के बीच पुरानी अदावत है।

मनोज धामा वर्तमान नगर पालिका चेयरमैन रंजीता धामा के पति है और उनके खिलाफ नगर पालिका में हुए 300 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच चल रही है। विधायक और पालिका चेयरमैन के बीच आए दिन के आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी से पार्टी की भी जमकर किरकिरी हो रही है।

लोनी विधायक का आरोप है कि अफसर विधायकों की सुनते नहीं हैं। वे जनता की आवाज उठाते हैं इसलिए अफसर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं जिसमें पार्टी के कुछ लोग भी शामिल हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ हो रहे विवादों से एक बात तो स्पष्ट है कि मामलें की जड़ में कहीं न कहीं भ्रष्ट अफसरशाही और सरकार से उन्हें मनमर्जी करने की छूट बड़ी वजह है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर के इस दर्द को समझा जा सकता है क्योंकि जब अधिकारी एक विधायक की नहीं सुन रहे तो आम जनता की हालत कैसी होगी इसे समझा जा सकता है।

वे अधिकारी जो भ्रष्ट संस्कृति के पोषक रहे है उनका सीधा काम है कि अगर एक कद्दावर नेता से किसी बात पर ठन जाए तो वे अपनी पंसद के किसी दूसरे कद्दावर नेता की शरण में पहुंच जाते हैं। लोनी विधायक के साथ चल रहा ताजा विवाद कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। लेकिन अंजाम भले ही कुछ हो मगर लोनी में चल रहे प्रकरण के कारण सरकार की खूब फजीहत हो रही है।

पहले पुलिस की मुठभेड़ के डर, अब नागरिकता कानून के विरोध में हुई गिरफ्तारियों से ओवरलोड कारागार

डासना जेल का बिगड़ा बजट

संवाददाता

गाजियाबाद। योगी सरकार में पुलिस की सख्ती का असर देखना है तो तो डासना जेल घूम आईए। जेल में सत्रह साल बाद कैदियों का आंकड़ा साढ़े पांच हजार को पार कर गया है। पिछले कुछ महीनों से अपराधियों के खिलाफ चल रहे पुलिस के अभियान के कारण पहले ही डासना जेल कैदियों से भरी थी। लेकिन इन दिनों नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रर्दशन व हिंसा करने वालों की गिरफ्तारी ने डासना जेल का बजट बिगाड़ दिया है। खान-पान से लेकर बैरको में रहन-सहन की व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। आलम यह है कि बैरिकों में कबूतरों की तरह कैदियों को ठुंसना पड़ रहा है। पहले ही एनकाउंटर के डर से कोई कोर्ट तो कोई पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर जेल पहुंच रहा था। कोई जेल से ही अपनी जमानत की फाइल को होल्ड करवा रहा था। पुलिस से बचने के लिए बदमाश खुद को जेल में ज्यादा सुरक्षित मान रहे थे इसलिए कुछ महीनों के दौरान गाजियाबाद की डासना जेल में कैदियों की संख्या का ग्राफ लगातार बढ़ता गया।

बढ़ रहा है बंदियों का ग्राफ

सरकारी रिपोर्ट पर गौर करें तो यूपी की जेलों में सुरक्षा की दृष्टि से डासना जेल अति संवेदनशील कैटेगरी में है। सबसे अधिक हाईप्रोफाइल कैदी यहां बंद है। 1997 में बनाई गई इस जेल की क्षमता 1704 कैदियों को रखने की ही है। लेकिन बनने से लेकर अब तक कैदियों का आंकड़ा तीन हजार से कम नहीं रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही पुलिस के डर से हिस्ट्रीशीटर ही नहीं माफिया भी जमानत तुड़वाकर डासना जेल पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि जेल में कैदियों की संख्या पांच हजार से ऊपर पहुंच गई है। लेकिन अचानक नागरिकता कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रर्दशन में हुई लोगों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी से जेल की व्यवस्था और ज्यादा चरमरा गई है। इन दिनों सर्दियों के अवकाश के कारण अदालतें भी बंद है। इसलिए जमानत पर हर रोज छूटने वाले औसतन सौ कैदियों की रिहाई भी इन दिनों बंद है। जेल प्रशासन लाचार है। बंदियों का आंकडा साढ़े पांच हजार से उपर पहुंच चुका है।

एक बैरक में 60 कैदियों की क्षमता

60 कैदियों की क्षमता वाले एक बैरिक में दो सौ से लेकर ढाई सौ तक कैदियों को रखना पड़ रहा है। सर्दी के कारण जेल में मिलने वाले गर्म कंबल और खाने का सामान वैसे तो प्रर्याप्त मात्रा में है। लेकिन जेल प्रशासन की परेशानी इस बात को लेकर है कि बंदियों की संख्या बढ़ जाने के कारण उनसे मुलाकात करने वाले मुलाकातियों की संख्या भी इन दिनों तेजी से बढ़ी है। हांलाकि जेलर आनंद शुक्ला का कहना है कि हम किसी भी हाल में जेल मेन्युइअल का सख्ती से पालन कर रहे हैं। बंदियों के खानपान और रहन सहन की व्य वस्थां जेल मेन्युअल के हिसाब से की जा रही है।

मोदी की रैली से दिल्ली बीजेपी को मिली संजीवनी

बीस साल का वनवास खत्म करने के लिए बन रही है रणनीति

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की अवैध कालोनियों को नियमित करने के बाद प्रधानमंत्री की धन्यवाद रैली से बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस की 15 साल की सत्ता और गत पांच सालों से आम आदमी पार्टी के शासन से मायूस हो चुकी राज्या बीजेपी में उत्साह का संचार हुआ है। पीएम मोदी ने धन्यवाद रैली के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर चुन चुन कर निशाने साधे।

दिल्ली में बीजेपी 20 साल से सत्ता का वनवास झेल रही है। ऐसे में बीजेपी इस बार दिल्ली के सियासी किले को हर हाल में फतह करना चाहती है। इसी वजह से बीजेपी की प्रदेश यूनिट के साथ-साथ केंद्रीय नेतृत्व ने मोदी की रैली के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव अभियान का बिगुल फूंकते हुए केजरीवाल की चुन चुनकर पोल खोली।

इस मौके पर राजधानी की 1731 कॉलोनियों को रेग्युलराइज करने को लेकर अनाधिकृत कॉलोनी के लोगों ने मंच पर जाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया। लोगों ने कच्ची कॉलोनियों को पक्की (वैध) करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद पत्र दिया। इस पत्र पर 11 लाख लोगों के दस्तखत थे। इस मौके पर दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने पीएम मोदी को 'भारत का आधुनिक लौहपुरुष' बताया।

2020 में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को मात देने के लिए बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में उतरने जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने चुनाव से ऐन पहले अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का बड़ा दांव चला है। बीजेपी इसे लेकर दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में माहौल बनाने में भी जुट गई है। इस बार दिल्ली चुनाव प्रभारी के साथ केन्द्रीय नेतृत्व जंबोजेट नेताओं को चुनावी तैयारियों के लिए मैदान में उतारने जा रहा है।

दिल्ली बीजेपी ने 'धन्यवाद रैली' को भुनाने के लिए अनाधिकृत कॉलोनियों में जन संपर्क और सभाएं करने की शुरूआत कर दी है। पार्टी के नेता चुनाव से पहले लोगों को पक्की रजिस्ट्री देने की योजना पर काम कर रहे है।

पीएम मोदी की रैली में जुटी करीब करीब एक लाख लोगों की भीड़ देखकर राज्यी बीजेपी के नेता गदगद है। बता दें कि दिल्ली की सियासी जंग फतह करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिल्ली के चुनाव में कई केंद्रीय मंत्रियों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रखी है। चुनाव प्रभारी का जिम्मा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर के पास है तो सह प्रभारी केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। मोदी के ये दोनों मंत्री लगातार दिल्ली में चुनावी रैलियां करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं।

झाड़ू से झाड़ू की सफाई

आम आदमी पार्टी का चुनाव निशान झाड़ू है और पहली बार जब आम आदमी पार्टी चुनावों में उतरी तो उसका नारा था - अब चलेगी झाड़ू। ये स्लोगन दिल्ली में जगह जगह और तकरीबन हर ऑटो रिक्शा के पीछे देखने को मिला था। जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, पूरे देश में स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया। फिर तो बीजेपी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नॉमिनेट किये जा रहे लोगों ने ऐसे झाड़ू उठाया कि लगा जैसे झाड़ू पर बीजेपी का ही कॉपीराइट हो। धन्यवाद रैली से पीएम मोदी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने उसी अंदाज में आप के चुनाव निशान को हाइजैक करने की कोशिश की है।

प्रधानमंत्री की बातों से तो ऐसा ही लगता है उन्हों ने रैली के अंत में कहा- 'मेरा आपसे आग्रह है कि दिल्ली के जिस भी इलाके में आप रहते हैं, वहां अगले एक हफ्ते तक सफाई अभियान चलाया जाये- नये साल का स्वागत और ज्यादा साफ सुथरी दिल्ली के साथ करेंगे।'

बात अगर दिल्ली में बीजेपी कार्यकताओं की करें तो ये बात भी साफ हो गई कि भले ही दिल्ली में कई क्षत्रप हो, लेकिन मोदी की रैली में जिस तरह से दिल्ली के नेताओं ने एकजुटता दिखाई उससे आम आदमी पार्टी को भी सकते में डाल दिया है। मोदी की रैली के बाद दिल्ली प्रदेश से लेकर भाजपा मुख्यालय में टिकट की चाह रखने वाले लोगों की भीड़ भी बढ़ गई है।

मनोज तिवारी ने केजरीवाल के वायदों को बताया चुनावी स्टंट

चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल सरकार की तरफ से लोगों को मुफ्त तोहफों के ऐलान पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तंज कसते हुए कहा है कि केजरीवाल पांच साल तक सोते रहे जब चुनाव आया तो उन्होंने अपने वादे याद आ गए। तिवारी का कहना है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है वो इस बार केजरीवाल के झांसे में नहीं आयेंगे।

पांच साल पूरे होने पर दिल्ली में फ्री वाई-फाई के ऐलान पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने जो वादा पांच साल पहले किया था उसे पूरा करने का आश्वासन आज तक दे रही है। दिल्लीवासियों को फ्री वाई-फाई देने का ऐलान अरविंद केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद ही हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक दिल्ली सरकार ने इस वादे को पूरा नहीं किया और अब चुनाव का समय नजदीक आने पर लोगों को गुमराह करने के लिए सरकार ऐसे ऐलान कर रही है।

58 महीनों के कार्यकाल में केजरीवाल सरकार ने सुविधाओं के नाम पर लोगों को सिर्फ आश्वासन ही दिया है। तिवारी ने कहा कि करीब दो महीने केजरीवाल सरकार के और बचे हैं, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फ्री वाई-फाई देने और इसके हॉट स्पॉट टावर लगाने का मात्र दावा कर रहे हैं, जबकि इतने कम समय में यह व्यावहारिक रूप से संभव ही नहीं है। यदि इतने समय में दिल्लीवासियों को वाई-फाई दिया जा सकता था तो इतने लम्बे समय तक इंतजार क्यों करवाया गया?

मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार को फ्री वाई-फाई देने के दावे के साथ दिल्ली की जनता को यह भी बताना चाहिये कि कौन सी कंपनी हॉट स्पॉट लगा रही है और उसका टेंडर कब किया गया। सिर्फ 100 जगहों पर हॉट स्पॉट लगाकर दिल्ली के लोगों को गुमराह करने की केजरीवाल की साजिश अब कामयाब होने वाली नहीं हैं। उन्होंने कहा कि फ्री वाई-फाई देने की घोषणा केजरीवाल का चुनावी स्टंट है।

ग्रहो के उलटफेर से भारत और विश्व की राजनीति में अस्थिरता के संकेत

सूर्य-शनि का साथ हो सकता है राजतंत्र के लिए अमंगलकारी

ग्रहों का उलटफेर इंसान के जीवन के साथ राजनीति में अपना प्रभाव छोड़ता है। इन दिनों भारत में जो उथल पुथल मची है वो बदलते ग्रहों का ही परिणाम है। 16 दिसंबर की दोपहर 15:28 बजे से धनु राशि पर एक माह के लिए सूर्य के साथ कई अन्य ग्रहों (शनि केतु गुरु तथा 17 दिसम्बर से बुध भी साथ आया है) का जमावड़ा हो चुका है। इनको राहु सर्वाधिक प्रभावित करेगा। वृश्चिक और मकर राशि पर भी ग्रह स्थित होंगे।

आचार्य निशांत भारद्वाज
(मो.- 9528425099)

ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है जब सूर्य-शनि एक राशि पर हों और अगल बगल की राशियों पर भी ग्रह संचार कर रहे हों तो यह स्थिति किसी भी तरह से मानव व जीव जंतुओं के लिए सुखदायी नहीं हो सकती।

यह संकेत भारत में शासकीय कूटनीति के साथ साथ विश्व राजनीति में भी उलटफेर या तख्तापलट की आशंकाओं को प्रबल करते हैं। बदले ग्रहों की दशा किसी ताकतवर राजनेता की हत्या या दुर्घटना से मृत्यु के भी संकेत देती है। बदलती स्थितियों में किसी भी देश की पूर्व सीमाओं में भी परिवर्तन संभव है।

इन बदते ग्रहों के कारण हिमपात, हिमस्खलन, अत्यधिक वर्षा, भीषण शीतलहर, धार्मिक नरसंहार, राजनैतिक ज्वालामुखी विस्फोट, भूकम्प, चक्रवात, और जीवनवायु की कमी, विषैली गैसों का संचार,

लूटपाट बलात्कार महंगाई, युद्ध आदि से जनता त्राहिमाम कर सकती है। विश्व 2 से 3 गुटों में विभक्त होता दिख सकता है। राजनीति और वैश्विक कूटनीति की पटकथा भी सूर्य के धनु और मकर संचार में ही लिखी जा सकती है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर स्मृति विशेष

यादों में 'अटल'

नवीन कुमार
प्रवक्ता भाजपा

सार्वजनिक जीवन से चौदह वर्ष तक नेपथ्य में चले गए अटल बिहारी वाजपेयी के अवसान पर देश विदेश में छाए अवसाद की सघनता से उनकी प्रभावशीलता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। उनके बारे में 1984 के चुनाव में बड़े–बड़े विपक्षी नेताओं के पराजित हो जाने के बाद एक भोजपुरी गायक ने जो पंक्तियां लिखी थीं उसकी सार्थकता भी साबित हो गई। अटल जी के बारे में उसने लिखा था– 'हारे अटल बिहारी वाणी के प्रवीण लोकसभा शून्य हो गई।' उनकी वाणी का प्रभाव बहुत लोगों ने जादुई शब्द से आंका है। लेकिन वे जादूगर की तरह कुछ क्षणों के लिए सम्मोहित नहीं करते थे। उनकी वाणी की प्रवीणता और आचरण की सार्थकता अनंतकाल के लिए प्रभावशाली बनी रहेगी। उनके राजनीतिक जीवन में अनेक चढ़ाव उतार आए, लेकिन अंतत: जवाहर लाल नेहरू द्वारा की गई भविष्यवाणी सार्थक साबित हुई। उन्होंने विदेशी राजनयिकों से अटल जी का परिचय कराते हुए कहा था, 'हियर इज ए यंग पार्लियामेन्टेरियन हू इज फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया' और वह ऐसे प्रधानमंत्री बने। उनके कृत्यों का प्रभाव ही था कि 10 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस 2014 में अपने लम्बे जीवन काल की सबसे बुरी पराजय की शिकार हुई और निरन्तर होती जा रही है। उनके नेपथ्य में चले जाने के बाद भी जिस प्रकार राजनीतिक व्यवहार और सामाजिक सौहार्द के लिए उनकी वाणी और आचरण को संसद और उसके बाहर उद्धृत किया जाता रहा है, वह इस बात का प्रमाण है कि वह सर्वाधिक जननायक थे।

अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे राजनीतिक व्यक्ति थे जिन्होंने उतार चढ़ाव की अनेक मंजिलों को बिना धैर्य खोए लांघा है। चाहे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद कतिपय बड़े नेताओं का जनसंघ छोड़कर जाना हो या फिर 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के महज दो सदस्यों का लोकसभा में पहुंचना या फिर 1962 का चुनाव हारना या 1980 में जनता पार्टी का अलग होना और 1984 में फिर चुनाव हारना। या फिर जनसंघ जैसी पार्टी का अध्यक्ष बनना, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद सुशोभित करना, 1977 में विदेश मंत्री बनना। संयुक्तराष्ट्र संघ में हिन्दी में भाषण देना। 1980 में जनता पार्टी के टूटने बिखरने और 1989 में महज एक वोट से लोकसभा में सरकार की पराजय या पांच वर्ष तक पहली गैर कांग्रेसी सरकार को सफलतापूर्वक चलाने में 24 दलों का साथ लेना हो– न तो किसी घटना पर उन्हें विषादयुक्त देखा गया और न ही वे प्रगल्भित होते थे।

अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार, लेखक, कवि और राजनेता की त्रिवेणी थे। ऐसा अद्भुत संगम किसी अन्य व्यक्तित्व में देखने को नहीं मिलता। कई बार उनकी सहज भाव से की गई अभिव्यक्तियों को न समझ पाने के कारण कुछ लोग यह भी कहने लगते थे कि उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निभ नहीं रही है। इसका उत्तर वह सदैव देते थे कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और जीवन के अंतिम क्षण तक संघ का स्वयंसेवक रहूंगा। वह जननेता थे। यही कारण है कि उनकी जन सभाओं को सुनने के लिए जो भारी भीड़ उमड़ती थी उनमें भाजपा और जनसंघ के अनेक विरोधी भी शामिल रहते थे। संसद हो या संसद के बाहर उन्होंने अपनी बात बेबाक ढंग से रखी लेकिन अभिव्यक्ति में शब्दों का चयन ऐसा रहा कि चोटिल होने पर भी लोग हंगामा नहीं कर पाते थे। ऐसा नहीं था कि वाजपेयी जी चिन्तित नहीं होते थे। समस्याओं पर वह चिन्तित अवश्य होते थे लेकिन उसके विषाद से अपने और आसपास के वातावरण को कभी बोझिल नहीं होने देते थे।

एक कवि के रूप में उनकी एक रचना जो संभवत: 60 साल पहले की है, आज के हिन्दुत्व के बारे में भारतीय जनता पार्टी और संघ के रुख को समझने में शायद मददगार साबित हो। उनकी वह कविता 'हिन्दू तन मन हिन्दू जीवन रग रग हिन्दू मेरा परिचय' जिसे गाकर उन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए, की एक पंक्ति है– 'कोई बतावे कब हमने काबुल में जाकर मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय' यही भारत की सनातन परम्परा रही है। और इस कविता के द्वारा अटल जी ने संघ की सनातन परम्परा के प्रति प्रतिबद्धता का उल्लेख किया है। राजनीतिक क्षेत्र में व्यस्तता के बावजूद सामाजिक सरोकार के साथ–साथ काव्य जगत में भी उन्होंने अपनी पैठ बनाई थी। कवि सम्मेलनों में उन्हें सुनने के लिए लोग दूर–दूर से आते थे। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन उनके सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी स्वभाव की सर्वत्र चर्चा हो रही है। राजनीति में जब आज घृणा का दौर चल रहा है और हठवादिता का अतिरेक है उस समय वाजपेयी जी द्वारा बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किए जाने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रति उनके उदगार इस बात का सबूत हैं कि क्यों उन्हें एक कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने संयुक्तराष्ट्रक संघ में उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सौंपा जिसमें उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य शामिल थे।

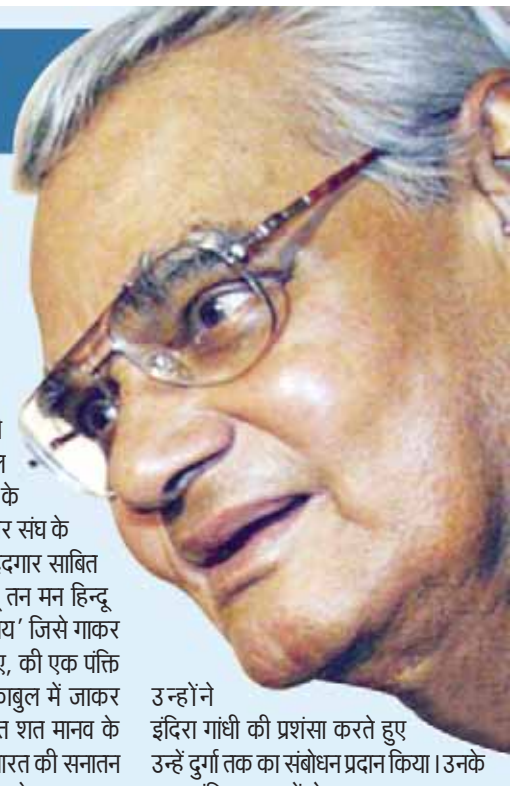

उन्होंने इंदिरा गांधी की प्रशंसा करते हुए उन्हें दुर्गा तक का संबोधन प्रदान किया। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में पोखरण का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ जिसकी भनक तक संसार को नहीं लगी थी। उन्होंने सबसे पहले उसकी जानकारी सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता सरदार मनमोहन सिंह को अपने यहां चाय पर बुलाकर दी थी। राजनीति में समाप्त हो रहे शिष्टाचार के काल में विपक्ष को विश्वास में लेने का उनका यह उदाहरण दिशाबोधक है। आज भारत सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी का देश बन गया है। इस पीढ़ी के आचरण और व्यवहार को प्रभावित कर अपनी साख जमाने के लिए राजनीतिक नेता प्रयत्नशील हैं लेकिन जिस व्यक्ति ने सर्वाधिक युवा मन को प्रभावित किया वे अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसीलिए लोग उन्हें वृद्धावस्था तक युवा हृदय सम्राट कहा करते थे। युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले ऐसे अटल जी को शत शत प्रणाम।

पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर विशेष

वो महामना जिन्होंने दिया बनारस विश्व विद्यालय

पं.शिवमोहन भारद्वाज

देश को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसा संस्थान देने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उनके जीवन पर कुछ बातें जानना बेहद जरूरी है। इलाहाबाद में 25 दिसंबर, 1861 में जन्मे पंडित मदन मोहन मालवीय अपने महान कार्यों के चलते 'महामना' कहलाए। मालवीय ने अपना करियर इलाहाबाद जिला विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में शुरू किया। महामना मदन मोहन मालवीय शिक्षाविद् थे। उन्होंने 1915 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की स्थापना की। मालवीय ने एलएलबी करके पहले जिला अदालत और उसके बाद 1893 इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत की। 1885 से 1907 के बीच तीन पत्रों– हिन्दुस्तान, इंडियन यूनियन और अभ्युदय का संपादन किया। 'नरम दल' और 'गरम दल' के बीच कड़ी का काम करते हुए स्वतंत्रता संग्राम के पथप्रदर्शकों में से एक बने। दक्षिणपंथी हिंदू महासभा के प्रारंभिक नेताओं में से एक मालवीय समाज सुधारक और सफल सांसद थे।

मालवीय 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में प्रेरक भाषण देते ही राजनीति के मंच पर छा गए। उन्होंने लगभग 50 साल तक कांग्रेस की सेवा की। कांग्रेस के चार बार अध्यक्ष रहे जिसमें 1909 (लाहौर), 1918 (दिल्ली), 1930 (दिल्ली) और 1932(कलकत्ता) शामिल है। उन्होंने अत्यंत प्रभावशाली अंग्रेजी समाचार पत्र 'द लीडर' की 1909 में स्थापना की जो इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। 1930 में जब महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और गिरफ्तारी दी। मालवीय इलाहाबाद नगरपालिका बोर्ड में सक्रिय रुप से शामिल रहे और वह 1903–1918 के दौरान प्रॉविन्शियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य, 1910–1920 के दौरान सेंट्रल काउंसिल, 1916–1918 के दौरान इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य रहे। उन्होंने 1931 में दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। 1937 में सक्रिय राजनीति को अलविदा कहकर और उन्होंने अपना पूरा ध्यान सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित कर दिया। विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन और बाल विवाह का विरोध करने के साथ ही उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया। 1946 में उनका निधन हो गया। 24 दिसंबर, 2014 को उनकी 153वीं जयंती से एक दिन पहले उनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था।

उनसे जुड़ीं कुछ खास बातें है जिन्हें जानना जरूरी है

भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य 'सत्यमेव जयते' (सच की जीत होती है) को लोकप्रिय बनाने का श्रेय उनको ही जाता है। 'सत्यमेव जयते' हजारों साल पहली लिखे गए उपनिषदों का एक मंत्र है।

मालवीय ने बीएचयू जैसे संस्थान के सपने को हकीकत में बदलने के लिए बहुत कठिन मेहनत की। जब उन्होंने यूनिवर्सिटी खोलने के लिए निजाम से आर्थिक मदद मांगी थी तो निजाम ने मदद देने से इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसके बाद फंड जुटाने के मकसद से मार्केट में अपने स्लिपर की नीलामी की। संयोग की बात है कि चप्पल की बोली उसी निजाम ने लगाई और उसे बड़ी रकम देकर खरीदा।

भले ही आज बीजेपी के लीडर उनसे ज्यादा करीब हैं और उनको अपना प्रेरणास्रोत मानते हैं। लेकिन वह वल्लभभाई पटेल की तरह ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिग्गज चेहरों में से एक थे। अक्सर मालवीय को हिंदू राष्ट्रवादी दिखाने की कोशिश की जाती है लेकिन उन्होंने हिंदू–मुस्लिम एकता के लिए काफी काम किए। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द पर दो प्रसिद्ध भाषण दिए जिनमें से एक भाषण उन्होंने 1922 में लाहौर में दिया था और दूसरा 1931 में कानपुर में।

जब मालवीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे तो उन्होंने गोरखपुर के चौरी चौरा घटना में आरोपी बनाए गए क्रांतिकारियों का केस लड़ा था। कहा जाता है कि उन्होंने 153 क्रांतिकारियों को मौत की सजा से बचाया था। उनकी जयंती पर देश उन्हें नमन करता है।

लेखक, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीहय महामंत्री हैं

कैसे टिके संकल्प 2020 पर

डा. रोहन राजपूत
(एक्टर व यूट्यूबर)

नमस्कार दोस्तों, नया साल आने वाला है। नए साल के साथ आता है न्यू ईयर का संकल्प। एक रिसर्च के मुताबिक अक्सर 55 फीसदी लोग 1 जनवरी को न्यू ईयर संकल्प लेकर 15 जनवरी तक भूल जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें इसमें आपको 3 टिप्स दूंगा कि कैसे आप 1 जनवरी 2020 के बनाए संकल्प पर 31 दिसंबर 2020 तक टिके रह सकते हैं।

टिप्स 1: अपने संकल्प को एक कागज पर लिखे और उस कागज को ऐसी जगह चिपका दें, जहां आप उसे रोजाना देख सके। उदाहरण के लिए अपने ऑफिस की डेस्क पर या आईने पर या अपने बेडरूम की दीवार पर ताकि सोते जागते समय आप उसे देख सके और याद रख सकें।

टिप्स 2: किसी शुभचिंतक की सहायता लें अपने तय किए गए गोल को पाने के लिए। वह शुभचिंतक आपका फैमिली मेंबर, दोस्त, रिश्तेदार या ऑफिस सहयोगी हो सकते हैं। जो हर समय आपको याद दिलाते रहें कि आपका लक्ष्य क्या है। आपको हर समय मोटिवेट कर सके, जैसे वे रोज सुबह आपको 5 बजे उठा सकें व्यायाम के लिए।

टिप्स 3: प्रयोगात्मक और वास्तविक गोल बनाएं, जो काल्पनिक ना हो ताकि आपको विश्वास हो कि आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। एक या दो गोल ही बनाएं ज्यादा नहीं और उन गोलू को दी रणता से पूरा करें यह गोल आपकी फिटनेस रिलेशनशिप हेल्थ फैमिली सोशल लाइफ यह कारोबार की बढ़ोतरी के हो सकते हैं।

क्यों उबल रहे हैं पूर्वोत्तर के राज्य

अरविंद शर्मा

मुद्दा

नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों को तमाम आश्वासन दिए लेकिन इसके बावजूद असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय उबल पड़े हैं। असम में छोटे-बड़े संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतर पड़े हैं। इनमें साहित्यकार, कलाकार, समाजसेवी, व्यापारी, छात्र समेत सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। कई जगह आगजनी भी हुई और गुवाहाटी में तो स्थिति बेकाबू हो जाने पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। हांलाकि फिलहाल पूर्वोत्तिर शांत है लेकिन विरोध की आंच अभी थमी नहीं हैं।

नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में बंद पिछले दस वर्षों में नार्थ-ईस्ट का सबसे प्रभावी बंद माना गया है। लोग नागरिकता संशोधन बिल वापस लेने और 'आरएसएस-भाजपा गो बैक' के नारे लगा रहे हैं। 11 घंटे के बंद को देखकर 70-80 के दशक के हुए असम आंदोलन की याद ताजा हो गई। बंद का आह्वान भले ही उत्तर-पूर्व छात्र संघ ने किया था लेकिन यह बंद आम लोगों का आंदोलन बन गया। प्रदर्शनकारियों ने असम के मुख्यमंत्री सवार्नंद सोनोवाल और कुछ अन्य मंत्रियों के घर पर प्रदर्शन किए, इस दौरान पथराव की घटनाएं भी हुईं। सवाल यह है कि पूर्वोत्तर के राज्य उबल क्यों रहे हैं?

नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हो जाने के बाद पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिमों को आसानी से नागरिकता मिल सकेगी। पूर्वोत्तर राज्यों के मूल निवासियों को डर है कि इन लोगों को नागरिकता मिलने से उनकी पहचान और आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। असम में नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध उसी दिन से शुरू हो गया था जब जनवरी 2019 में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था, तब भाजपा सरकार के सांझीदार असम गण परिषद ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तब लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के कारण ?विधेयक निरस्त हो गया था।

असम में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा दशकों से प्रभावी रहा है जिसके लिए 80 के दशक में चले असम आंदोलन के परिणामस्वरूप हालात बेकाबू हो गए?थे। तब तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने आंदोलनकारी संगठनों से बातचीत कर असम समझौता किया था। असम समझौते में 24 मार्च, 1971 की तारीख को कट आफ माना गया था और तय किया गया था कि इस समय तक असम में आए हुए लोगों को ही यहां का नागरिक माना जाएगा। हाल ही में पूरी हुई एनआरसी की प्रक्रिया का मुख्य बिन्दु भी यही कट ऑफ तारीख है। इसके बाद राज्य में आए लोगों को विदेशी माना जाएगा।

नागरिकता विधेयक को लेकर विरोध भी इसी बिन्दु पर है क्योंकि विधेयक में 31 दिसम्बर, 2014 तक भारत में आए लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में अवैध बंगलादेशियों की घुसपैठ के चलते कई क्षेत्रों की जनसांख्यिकी में फेरबदल हो चुका है। असम के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो गए हैं और घुसपैठिये बहुसंख्यक। मूल असमी नागरिकों का कहना है कि जब असम के लिए एक कट ऑफ तारीख तय है तो हिन्दू बंगलादेशियों को नागरिकता देने के लिए विधेयक क्यों लाया गया।

विधेयक को लेकर असम की ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी के रहने वाले लोगों में भी मतभेद है। बंगाली प्रमुख वाली घाटी विधेयक के पक्ष में दिखी। स्थानीय लोगों को डर है कि अब अन्य देशों के लोगों को यहां बसा कर मूल लोगों और उनकी भाषा को विलुप्त प्रायः बना दिया जाएगा, साथ ही उनकी आजीविका पर भी संकट ?खड़ा हो जाएगा। त्रिपुरा के कुछ भाग छठी अनुसूची के अन्तर्गत आते हैं लेकिन जनजातीय बहुल इस राज्य में भी नागरिकता संशोधन विधेयक का जोरदार विरोध हो रहा है। सबसे अधिक विरोध त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हो रहा है। अलग तिप्रालैंड राज्य की मांग उठाई जा रही है। विरोध का आधार जनजातीय पहचान को होने वाला खतरा है।

कई जनजातीय संगठन भी विरोध पर उतर आए हैं। उनका मानना है कि इस विधेयक के पारित होने से सीमा पार से घुसपैठ और बढ़ जाएगी। त्रिपुरा पूर्वोत्तर का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बंगलादेश के गैर आदिवासियों की बड़ी आबादी आने के चलते आदिवासी आबादी अल्पसंख्यक हो गई है। मणिपुर और मिजोरम में भी लोगों में खौफ पैदा हो चुका है। इन्हें डर है कि इस विधेयक से बंगलादेश से अवैध रूप से आए चकमा बौद्धों को वैधता मिल जाएगी। नगालैंड और मेघालय में भी ऐसी ही आशंकाएं हैं, अरुणाचल और सिक्किम में भी विरोध हो रहा है।

पूर्वोत्तर के संगठनों का कहना है कि भाजपा यहां एक तीर से कई निशाने साध रही है। एक तरफ यहां अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशियों के निर्वासन की बात कर असम में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर नागरिकता संशोधन विधेयक पारित करा कर हिन्दू वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। पूर्वोत्तर का मामला जटिल दिखाई देता है और अब केन्द्र सरकार पर पूर्वोत्तर में शांति स्थापना का दायित्व भी है। देखना होगा कि विरोध किस तरह शांत होता है।

अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएं तो मोदी सरकार सबसे लाजवाब

सुनील कुमार वर्मा

चिंतन

पहली बार इस देश में कोई? ऐसी सरकार आई है जो हिंदुस्तान के नाम की सार्थकता को प्रमाणित कर रही है। हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक हिंदू पहले हैं इसके बाद जात-पात और मजहब की बात आती है। जिस देश में धारा 370 को जम्मू-कश्मीर से खत्म कर दिये जाने की हिमाकत करने वाली मोदी सरकार हो तो उससे ज्यादा उम्मीदें हर कोई रखेगा ही। जिस देश में 100 साल से भी ज्यादा मंदिर-मस्जिद विवाद को लेकर लफड़ा चल रहा हो और वहां कानून के दायरे में सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट का ऐलान कर दे तो उस सरकार से उम्मीदें हर कोई लगायेगा ही।

जिस देश के असम जैसे राज्य में अगर घुसपैठियों की संख्या वोटर के रूप में बन जाये और वे सभी मुसलमान हों तो देश के हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने का खतरा पैदा हो जाये तो वहां एनआरसी अर्थात नेशनल सिटीजन रजिस्टर लाना कोई? बुरी बात नहीं। इतना ही नहीं अब तो एनआरसी पर संशोधन विधेयक लाकर सरकार ने इसे संविधान के दायरे तले लोकसभा और राज्यसभा में पारित भी करा लिया है तो इस सरकार से हर किसी की उम्मीदें ज्यादा होंगी ही। अगर मोदी सरकार मुसलमानों से जुड़े एक मामले तीन तलाक को खत्म करने के लिए कानून ला सकती है तो लोगों की इस सरकार से उम्मीदें बढ़ेंगी ही।

हम मानते हैं कि शहीदे आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू के देश में सरदार पटेल जैसे मजबूत इरादे लेकर राष्ट्र के लिए काम करने जैसी ललक लेकर अगर पीएम मोदी और गृहमंत्री के रूप में अमित शाह डटे हुए हैं तो ऐसा उदाहरण अब तक कभी नहीं मिला। इनकी कर्त्तव्य परायणता और काम करने के अंदाज की जितनी तारीफ की जाये वह कम है। पर एक अहम चीज के बारे में देशवासी अगर चिंता कर रहे हैं और बराबर सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं शेयर कर रहे हैं तो वह आर्थिक मोर्चा है। इस सरकार को आर्थिक मौर्चे पर अभी बहुत कुछ करना है।

जीडीपी बहुत नीचे है, महंगाई की बात तो छोड़ो प्याज तक सेंचुरी मार चुका है। सोने-चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं। रियल स्टेट जगत में उदासी छायी है। नोटबंदी के बाद पैसा बाजार से गायब है। लोगों की जेबें खाली हैं और उद्योगपति अडानी को 1.40 हजार करोड़ के नए ठेके सरकार ने दिए हैं। अगर ऐसा है तो विपक्ष इस सरकार को पूंजीपतियों की सरकार ही कहेगा। लिहाजा सरकार को अपनी छवि सुधारनी होगी। पूरी अर्थव्यवस्था बैठ रही है यह बात हम नहीं लोग कह रहे हैं और लोगों की इस चिंता में हम भी हमसफर हैं।

इसीलिए हमारा यह मानना है कि इस समय आर्थिक मोर्चे पर सरकार की पहली प्राथमिकता अगर कोई होनी चाहिए तो वह बेरोजगारी को दूर करने को लेकर होनी चाहिए। हालांकि सरकार इसमें जरूर चिंतित होगी लेकिन लोगों की उम्मीद काम करने वाली मोदी सरकार से इसलिए ज्यादा है कि वह राष्ट्रभक्ति, कर्त्तव्यपरायणता और हिंदुत्व को लेकर परिणाम दे चुकी है। लोग अब आर्थिक मोर्चे पर बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं। इस परिणाम के अच्छा निकलने से लोग खुश हो जायेंगे। लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कि व्यापारी व उद्यमी हर कोई जीएसटी की जटिलताओं से परेशान है।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी पंजाब के बाद भाजपा के हाथ से निकल गए और हाल ही में महाराष्ट्र भी निकल गया। हरियाणा बाल-बाल बच गया। झारखंड पर खतरा मंडरा रहा है। अगर सोने-चांदी की कीमतों पर नियंत्रण हो जाये, रियल स्टेट अर्थात प्रोपर्टी की खरीद-फरोख्त में तेजी आ जाये, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जायें, पैट्रोल-डीजल के मूल्य कंट्रोल हो जाये तो लोगों को और क्या चाहिए। यही तो परिणाम है। महंगाई काबू में रहे जीडीपी डाउन न रहे और विकास दर चढ़ती रहे और सरकार को इसके लिए दावा न करना पड़े तो हर कोई ?मान लेगा कि अर्थव्यवस्था पटरी पर है।

जो हकीकत में इसके उलट है। कृषि, फसल और किसान के मुद्दे या फिर काला धन ये सब अर्थव्यवस्था से जुडे.मुद्दे हैं, हमें इस मामले पर सरकारी तंत्र से किसी भाषण की उम्मीद नहीं बल्कि परिणाम की जरूरत है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह सरकार सब कुछ कर सकती है बस इस में बहुत सुस्त है जिससे अर्थव्यवस्था नोटबंदी के बाद डाउन चल रही है। बाजार में नकदी का प्रवाह कम है और प्राइवेट सैक्टर अगर चिंतित है तो कल सरकारी सैक्टर के तहत भी चिंता की आग आगे बढ़ सकती है। रुपया डालर की तुलना में जमीन फाड़ कर नीचे जा धंसा है।

सरकारी कंपनियां जिस तरह से बैठ रही हैं वह भी लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं। हमारा मानना है कि अगर आर्थिक मुद्दे पर मोदी सरकार आगे बढ़ लें तो अब तक गुड से बैटर बनने वाली मोदी सरकार बहुत जल्दी बेस्ट भी बन जायेगी। लोगों को इसका इंतजार है पर हम भी यही कहेंगे कि लोगों की मांग भी यही है और सही समय पर अगर परिणाम निकल जाये तो फिर मोदी सरकार न सिर्फ भारत के नक्शे पर बल्कि पूरी दुनिया में एक नजीर बनकर स्थापित हो जायेगी।

यूपी सरकार और गाजियाबाद प्रशासन के प्रयास ला रहे बदलाव

2020 में बदल जाएगी गाजियाबाद की तस्वीर

- इन्फ्रास्ट्रक्चर के काम में तेजी
- सिग्नेचर प्रॉजेक्ट के काम होंगे पूरे
- स्वास्थ्य सेवाओं का मिलेगा तोहफा

विशेष संवाददाता

गाजियाबाद। नए साल 2020 में गाजियाबाद की तस्वीर बदली हुई दिखेगी। उत्तर प्रदेश शासन और जीडीए जनपद में तेजी से विकास कार्यों को अंजाम दे रहा है। इसके चलते गाजियाबाद जल्द ही सूबे का अव्वल जिला बन जाएगा। जीडीए वीसी कंचन वर्मा और जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय विकास कार्यों की लगातार समीक्षा करते हुए तय समय पर सभी प्रोजेकटों को पूरा करने पर जोर दे रहे हैं। मेयर आशा शर्मा और सांसद वी के सिंह भी जिले में मूलभूत सुविधाओं के लिए शासन स्त र पर अपने प्रयास कर रहे हैं।

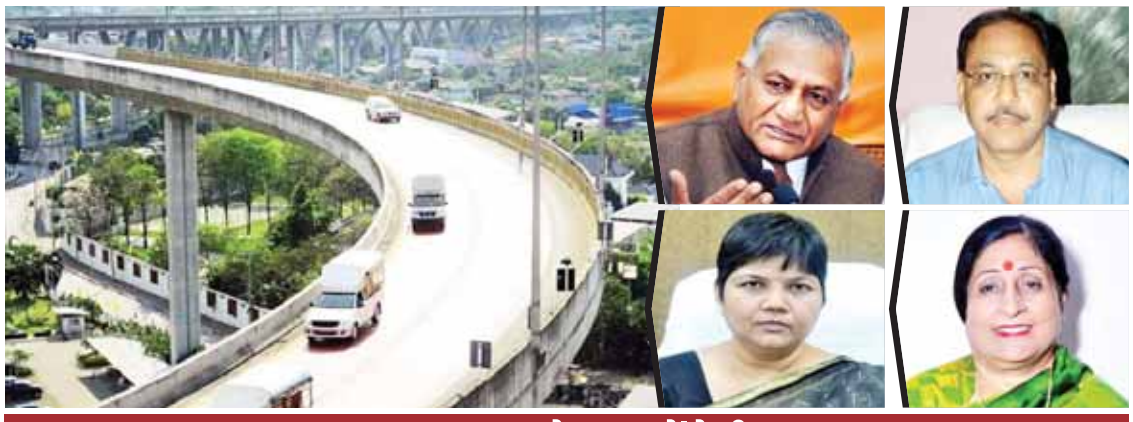

इन्फ्रास्ट्रक्चर के काम में तेजी

इसके अलावा एनएच 24 को मेरठ तक जोड़ने का काम डासना तक अगले छह माह में पूरा लिया जाएगा। जिसके बाद इस सड़क पर सरपट गाड़ियां दौड़ेंगी। राजनगर एक्टेंशन से दिल्ली गेट तक जाने वाले ऐलिवेटिड रोड को डीएनडी फ्लाई ओवर तक जोड़ने का काम भी अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा मैट्रो के विस्तार तथा सेक्टर 62 मैट्रो को गाजियाबाद तक पहुंचाने का काम भी अगले साल में आगे बढ़ सकता है। विकास के इन तमाम कामों के बाद गाजियाबाद जिले में विकास की एक नई तस्वीर देखने का मिलेगी।

जीडीए आने वाले साल में अपने 4 सिग्नेचर प्रॉजेक्टों को पूरा कर लेगा। इसके लिए प्राधिकरण ने शासन को एक रिपोर्ट बनाकर भेजी है। इनमें मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में बनने वाला एक्सपो एंड एग्जीबिशन सेंटर, इंटिग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस), हिंडन पुल और मधुबन बापूधाम में बनने वाला आरओबी शामिल है। जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने सभी प्रॉजेक्ट इंजीनियर्स को समय के भीतर काम करने के निर्देश दिए हैं। जीडीए के अधिकारियों का कहना है कि इन प्रॉजेक्टों के पूरा होने से गाजियाबाद की एक अलग पहचान बनेगी, इसलिए इन्हें सिग्नेचर प्रॉजेक्ट की श्रेणी में शामिल किया गया है।

बुनकरों के लिए बनेगा बाजार

मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में 152.65 करोड़ रुपये खर्च करके एक्सपो एंड एग्जीबिशन सेंटर तैयार किया जा रहा है। इससे गाजियाबाद को एक अलग पहचान मिलेगी। इसे आम बोलचाल में बुनकर मार्ट कहा जाता है। यहां देश के अलग-अलग हिस्सों के बुनकरों को एक बाजार मिलेगा। प्रॉजेक्ट 27 मार्च 2016 में शुरू हुआ था। 31 मार्च 2020 इसकी डेडलाइन तय की गई है।

आईटीएमएस जाम से दिलाएगा राहत

आईटीएमएस प्रॉजेक्ट लागू होने से गाजियाबाद की जाम के रूप में बनी छवि बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि आईटीएमएस से ट्रैफिक नियमों का पालन करना लोगों की मजबूरी होगी। नियम तोड़ते ही कैमरे की नजर में आएगा और चालान घर पहुंच जाएगा। इसका जुलाई में टेंडर फाइनल हो जाएगा। 30 जून 2020 तक इसे चालू किया जा सकेगा।

हिंडन पुल बनने से जाना होगा आसान

गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एनएच-58 पर हिंडन नदी का पुल टूट गया है। इसको तोड़कर नया पुल बनाने की तैयारी चल रही है। सेतु निगम के साथ 20 करोड़ रुपये का एमओयू हो गया है। सेतु निगम ने इसके ध्वस्तीकरण का काम भी शुरू कर दिया है। इसके खुलने के बाद यहां लगने वाले जाम और एक ही पुल पर आने वाले लोड की समस्या खत्म हो जाएगी। इसे 31 मई 2020 में पूरा किया जाएगा।

आरओबी बनने से मधुबन बापूधाम गुलजार

मेरठ रोड से सही तरीके से कनेक्टिविटी नहीं होने से जीडीए की मधुबन बापूधाम आवासीय योजना फ्लॉप होने की स्थिति में है। इसके लिए जीडीए ने यहां पर आरओबी बनाने का फैसला किया है। इस पर आने वाली लागत की डिटेल तैयार की जा रही है। इस प्रॉजेक्ट को भी सितंबर 2020 तक पूरा किया जाएगा।

मधुबन बापूधाम योजना में विकास कार्यों को तेजी से पंख लगें हैं। जीडीए ने मुआवजा वितरण की प्रक्रिया के बाद जमीन पर कब्जा लेना शुरू कर दिया है। अब तक जीडीए की ओर से करीब 40 एकड़ जमीन पर कब्जा लेने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

जिले में बन रहा कोटला के बाद दूसरा बड़ा स्टेडियम

इसके अलावा बीसीसीआई व जीडीए के प्रयासों से जिले में 45 हजार दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम बनाया जा रहा है। जिस पर करीब 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह दिल्ली-एनसीआर में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। हांलाकि कुछ तकनीकी कारणों से अभी तक स्टेडियम का नक्शा पास नहीं हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि ये बाधाए जल्द दूर हो जायेंगी। काम पूरा करने के लिए 2020 की डेडलाइन रखी गई है लेकिन डेडलाइन अब चार महीने बढ़ सकती है।

स्वास्थ्य सेवाओं का मिलेगा तोहफा प्रशासन और क्षेत्र के सांसद वीके सिंह के प्रयासों से अब शहरी क्षेत्र में दो नए अस्पतालों का रास्ता भी साफ हो गया है। एक अस्पताल के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा भी जा चुका है। यदि सब कुछ सही रहा और समय से हुआ तो नए साल में दोनों अस्पतालों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा।

बता दें कि शहरी क्षेत्र में 4 नए 50-50 बेड के अस्पतालों को बनाने के लिए लंबे समय से कवायद चल रही थी। इनमें से लोनी में बनने वाले अस्पताल का 60 प्रतिशत काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन खोड़ा, वसुंधरा और विजयनगर में बनने वाले अस्पतालों की फाइलें अभी अटकी हुई हैं। सीएमओ डॉ. एनके गुप्ता के मुताबिक खोड़ा में बनने वाले 50 बेड के अस्पताल के लिए खोड़ा नगर पालिका की ओर से 1.5 एकड़ जमीन अस्पताल के लिए प्रस्तावित की गई है। जिसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रपोजल बनाकर शासन को भेजा गया है। फिलहाल शासन से अनुमति नहीं मिल सकी है। शासन से अनुमति मिलने के बाद अस्पताल बनने में आने वाला खर्चा और स्टाफ की जरूरत और खर्च का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा जाएगा। शासन से बजट मिलने पर अस्पताल का काम शुरू हो सकेगा। सीएमओ ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। इसके अलावा विजयनगर में प्रस्तावित अस्पताल के लिए नगर निगम ने 2 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा था, जिस पर सहमति बन गई है। नगर निगम में हुई बोर्ड बैठक में पास किए गए प्रस्ताव की अभी स्वास्थ्य विभाग को लिखित में कोई सूचना नहीं मिली है। इसके अलावा बोर्ड बैठक के मिनिट्स भी प्राप्त नहीं हो सके हैं।

लिखित रूप में सूचना मिलने पर विभाग की ओर से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। सीएमओ ने कहा कि अगले 6 महीने में दोनों अस्पतालों का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है।

नागरिकता कानून व एनआरसी पर देशव्यावपी विरोध के बीच गाजियाबाद ने पेश की शांति की मिसाल

डीएम-एसएसपी की मेहनत से जिले में रही शांति

संवाददाता

गाजियाबाद। नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में देशभर मे हो रहे विरोध का असर गाजियाबाद में भी रहा। लेकिन इस दौरान गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन ने बेहद मुस्तैदी के साथ न सिर्फ मामले को हैंडल किया बल्कि प्रदर्शनकारियों को भी काबू किया। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण काम को पूरा करने में एसएसपी और डीएम की मेहनत का सबसे अहम रोल रहा।

देश के कई इलाकों की तरह नागरिकता संशोधित बिल व एनआरसी के विरोध में जुमे की नमाज के बाद कई स्थानों पर हुए हंगामे व पत्थरबाजी के बावजूद गाजियाबाद जिला

शांत रहा। हांलाकि प्रशासन ने इस दौरान कुछ घंटो के लिए इंटरनेट जरूर बंद की थी ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। एहतियात के तौर पर स्कूल कालेजों की छुट्टी भी की गई थी। जिले में तनावपूर्ण शांति के बीच स्थित पूरी तरह नियंत्रण में रही। शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षबलों का गश्त लगातार जारी है। हालात पर नजर रखने के लिए खुद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय और एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने लोनी समेत पूरे जिले का दौरा किया। साथ ही पुलिस ने बवाल करने के आरोप में कई राजनितिक दलों से जुड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

हांलाकि तमाम प्रयासों के बाद भी पिछले जुमे की नमाज के बाद कैला भट्टा, ट्रांस हिंडन क्षेत्र के पसौंडा, मुरादनगर व लोनी में प्रदर्शन करने वाले लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। जिसमें कई पुलिस कर्मी भी घायल हो गए थे। हालात की नजाकत को भांपते हुए जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय और एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने अपने स्तर पर लोगों को समझाया और क्षेत्र के गणमान्य लोगों को साथ लेकर लोगों को समझाने में सफलता हासिल कर ली।

शासन के आदेश पर अब पुलिस पर पथराव की वारदात के बाद लोगों की गिरफ्तारियां शुरू की है। लगभग साढ़े तीन हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गयी है। पूरे जिले में भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त किए गए हैं। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय का कहना है कि जिले में पूरी तरह से शांति है फिर भी एतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढाई गयी है औ? लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। लोगों को भडकाने वाले नेताओं और सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक विनीतकांत पाराशर द्वारा भारद्वाज प्रिंटर्स, शॉप नं. 1, प्रिया सिनेमा मार्केट, मुरादनगर, गाजियाबाद से छपवाकर सैकेंड ए-288 नेहरूनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से प्रकाशित किया। संपादक विनीतकांत पाराशर, RNI: UPHIN/2017/74151 प्रशासनिक कार्यालय : ए-288 नेहरूनगर द्वितीय, गाजियाबाद।